ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, **AKBAR ROAD, NEW DELHI**
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **03 January, 2021**

Prof. Gourav Vallabh, Spokesperson, AICC addressed media at AICC Hdqrs., today.

प्रो. गौरव वल्लभ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी साथियों को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये नव वर्ष हम सबके लिए और अखंड भारतवर्ष के लिए मंगलमय हो।

39 दिन हो चुके हैं, 57 से ज्यादा लोगों ने शहादत दे दी। करनाल के संत बाबा राम सिंह जी, फाजिल्का से अमरजीत सिंह जी और कल उत्तराखंड के हमारे किसान भाई कश्मीर सिंह जी ने किसानों के समर्थन में अपनी देह त्याग दी है। इसके अलावा 57 से ज्यादा लोग दिल्ली के बॉर्डर पर इस कड़कड़ाती ठंड और बारिश में अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए। सरकार बात करती है, फिर 5 दिन आगे की एक नई डेट दे देती है। सवाल ये नहीं है कि 5 दिन बाद ही क्यों, हो सकता है कि सरकार की नए वर्ष की व्यस्तताएं हों, उनके कार्यक्रम हो, नया वर्ष मनाना हो मंत्रियों को, इसलिए उनके पास समय न हो, तो वो प्रतिदिन बात न कर पाएं। जब भी सरकार बात करती है, 5 दिन आगे की डेट दे दी जाती है। मैं आज उस विषय पर बात नहीं करुंगा। सबसे पहले तो सभी शहीदों को और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बॉर्डर पर लोग, जिनका देहांत हो रहा है, स्वर्गवास हो रहा है, उनको शहीद मानता हूं। उन शहीदों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, जो संत, जो किसान, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए इस आंदोलन को ताकत देने के लिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात प्रारंभ करुंगा।

कल जब शहीद भाई, किसान भाई कश्मीर सिंह जी ने शहादत दी, तो उनके नोट में क्या लिखा था कि कब तक हम इस सर्दी में बैठेंगे, ये सरकार सुन नहीं रही, इसलिए जान दे रहा हूं ताकि कोई हल निकल सके। ये उनका नोट था, जो उन्होंने छोड़ा है। उसी नोट को आगे ले जाते हुए मैं इस निष्ठुर और निर्दयी सरकार को कुछ बातें बताना चाहता हूं और सारी बातों के तथ्य हैं, आपको जो प्रेस नोट मिलेगा, उसमें उन सारे आंकड़ों का लिंक होगा।

एक तरफ तो जो किसान बैठे हैं, चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डरों पर, भले ही वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाला बॉर्डर हो, पंजाब-हरियाणा से दिल्ली आने वाला बॉर्डर हो, राजस्थान से दिल्ली आने

वाला बॉर्डर हो, लाखों की संख्या में किसान वहाँ पर बैठे हैं, उनकी बात, उनके प्रति सरकार की कोई, किसी भी तरह की उनके प्रति एंपेथी (Empathy) नहीं है, एपेथी (Apathy) है। तो मेरी आज की प्रेस वार्ता का टाईटल है – Apathy for Farmers and Empathy for Suit-boot Friends और मैं दोनों को प्रूफ करुंगा आज।

आरंभ करुंगा मैं वर्ष 2016 से और कंपनी का नाम है AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और सारे आंकड़े दूंगा और उन्हीं के वेबसाइट से निकाले हुए आंकड़े, उन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्यौरे दिए, उनसे आंकड़े निकाल कर आपके सामने रखुंगा। ये AALL कंपनी 2016 में, स्टॉक एक्सचेंज को जो प्रेजेंटेशन देती है, उसमें कहती है कि हमने जो अडानी पोर्ट SEZ एक कंपनी है, उसने AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड़ को इवेल्यूएट किया और 2017-18 में उन्होंने कहा कि हमें बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं आगे। ये सब उसका स्टॉक एक्सचेंज में ब्यौरा है। "Sizeable business with new contracts, we become a sizeable business with new contracts." 2017-18 में उन्होंने अपने प्रेंजेटेशन में लिखा। 2017-18 में वो लिखते हैं कि हमें अब स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और पोटेंशल साइट हमें आईडेंटिफाई करनी चाहिए, हमारे लॉजिस्टिक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए।

सुनिएगा, अभी बात सिर्फ चालू हुई है, क्रोनोलॉजी समझिए। 2016 में एडानी SEZ जो पोर्ट कंपनी है, वो इसको AALL को रिव्यू करती है। 2017-18 में उनको लगता है कि आगे आने वाला भविष्य सुनहरा है। हमें बहुत अच्छा बिजनेस और बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं और उसके लिए वो लॉजिस्टिक बिजनेस को स्ट्रीम लाइन करने का प्रोसेस चालू करते हैं। 2017-18, 2018-19 में उन्हें स्टोरेज के ठेके मिलते हैं, कई राज्य सरकारों से, जिनका ब्यौरा भी मैं दूंगा। अब खास बात सुनिए, जिसका जो मूल मंतव्य है आज की प्रेस वार्ता को, वो ये है कि भारत सरकार AALL, जिसका मतलब अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड़ है, भारत सरकार उनको स्टोरेज का प्रति टन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो गारंटी करती है। ये भारत सरकार गारंटी देती है उनको कि आपको प्रति टन इतना पैसा तो देंगे ही और एक साल के लिए नहीं, दो साल के लिए भी नहीं, 30 साल के लिए। 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार को अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड़ गारंटी करके देती है कि हम आपसे इतना स्टोरेज, आपने जो स्टोरेज बनाया है, उसका करेंगे ही और ध्यान रहे, जो ये गारंटी का पैसा है, ये प्रतिवर्ष इनफ्लेशन के आधार पर बढ़ेगा भी।

एक तरफ तो किसान जो आज 39 वें दिन अपनी एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए 57 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। 3 लोगों ने अपने शरीर त्याग दिए उनके समर्थन में, उनको गारंटी नहीं मिलती है। 30 साल की गारंटी मिलती है, AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड़ को और गारंटी मिलने के बाद, 30 साल के बाद ना केवल गारंटी रेवेन्यू की, ना केवल गारंटी, प्रतिवर्ष रेवेन्यू को इनफ्लेशन से लिंक कर दिया गया है कि जैसे-जैसे इनफ्लेशन होगा इकॉनमी में, उनका रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा।

आदरणीय सरकार, आदरणीय नरेन्द्र तोमर जी, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्या किसान अपनी जो बात को लेकर सीमाओं पर बैठे हैं, क्या उनको एमएसपी की लीगल गारंटी with the same inflation clause नहीं दी जा सकती हैं? आप 30 साल की गारंटी दे देते हो एक बिजनेस की अपने दोस्तों को और किसान की बात तक सुनने के लिए आपको 5-5 दिन का समय नहीं मिलता। भयंकर बारिश, ठंड में इस विपरीत हालात में किसान अपने बॉर्डरों पर बैठा है, दिल्ली आने के लिए वो वहाँ बैठा है, वो अपनी बात सुनाने के लिए बैठा है। आप 5-5 दिन गायब हो जाते हैं, बीच में, 22 दिन तक आपने कोई वार्ता नहीं की उनसे?

दूसरी बात और ये भी बहुत आज का महत्वपूर्ण तथ्य है। छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ में पहले ये बोला गया किसानों को, सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कि 60 लाख मीट्रिक टन धान हम खरीदेंगे। तो किसानों ने जो राज्य सरकार खरीफ का जो आउटपुट होता है, जिसको सेंट्रल पूल की परचेज कहते हैं, उसके अनुसार उन्होंने एक मंतव्य जाहिर किया। तो राज्य सरकार ने उस आधार पर चालू किया प्रोक्योरमेंट। 60 लाख मीट्रिक टन की बात करने वाले जो राइस की प्रोक्योरमेंट की बात करने वाले 47 लाख मीट्रिक टन के बाद बोलते हैं कि अब रखने की जगह नहीं है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बार-बार देश को आकर बोलते हैं कि हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट को कोई चिंता नहीं है, कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है, तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्यों रोका गया है? छत्तीसगढ़ में ये किसानों को वापस क्यों लौटाया जा रहा है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है, इसका मतलब आपने अभी तक प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं किया है। आपने चावल का प्रोक्योरमेंट 60 लाख मीट्रिक टन का जिसका आपने मंतव्य जाहिर किया था, वो अभी तक आपने चालू नहीं किया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने 47 लाख मीट्रिक टन 12 लाख फॉर्मर से अभी तक खरीदा, पर उसके बाद अब बोलते हैं कि हमारे पास खरीदने की जगह नहीं है। क्या जब ये AALL, ये स्टोरेज बनाएगा, तभी खरीदने की जगह आएगी क्या? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी ये AALL की, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, ये छत्तीसगढ़ में अभी इनके स्टोरेज नहीं है, क्या ये स्टोरेज बनेंगे, तभी आप वहाँ के किसानों का स्टोर करोगे एफसीआई के माध्यम से, जब आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट करोगे?

एक तरफ एमएसपी की लीगल गारंटी पर बात नहीं बनाई जाती है, दूसरी तरफ बार-बार किसानों को कहा जाता है कि हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट कभी खत्म नहीं होगा, ये क्या हो रहा है और ये तो उस समय के हालात हैं, जब 39 दिनों से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। उस समय ये हालात हैं, उसके अलावा क्या होता होगा, आप और मैं समझ सकते हैं, इस किसान की व्यथा को समझ सकते हैं। इसलिए मैं बार-बार, लोग कहते हैं कि सरकार किसानों को बिल समझा नहीं पा रही है, मैं कहता हूं किसान इस बार पूरी तरह से, बिल में जो लिखा हुआ है और बिल के जो भाव हैं, दोनों को समझ

चुके हैं। देश आज उनके साथ इसलिए खड़ा है, क्योंकि ये जिस तरह से रोज, प्रतिदिन चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं।

मध्यप्रदेश के उदाहरण आज सबसे छुपे नहीं हुए हैं। मध्यप्रदेश में 250 से ज्यादा, एग्जेक्ट बताऊं तो 269 सरकारी कृषि उपज मंडियों में से पिछले 6 महीने में 47 कृषि उपज मंडियां बंद हो गई। 143 कृषि उपज मंडियों के ट्रांजेक्शन 50 प्रतिशत से कम हो गए। देवास की बात बता रहा हूं आपको, मध्यप्रदेश के देवास में एक घटना घटित होती है और ये घटना आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नए-नए जो कृषि बिल हैं, उनकी बात कही जा रही है। देवास की घटना में ये कहा जाता है कि 22 किसानों से 2,581 क्विंटल दलहन खरीदने की बात की जाती है और 2 करोड़ रुपए की, उसकी वेल्यू होती है, वो जो व्यापारी है, वो किसानों की उपज लेकर फरार हो जाते हैं और ये वहाँ पर खरीदा 2,500 क्विंटल से ज्यादा उनसे दलहन खरीदा गया। मध्यप्रदेश में ये हो रहा है।

आज के एक और समाचार पत्र से आपको बताता हूं। मध्यप्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनियों ने फसल लगवाई, लेकिन क्वालिटी का हवाला देकर अब खरीदने से आना-कानी कर रहे हैं। यही तो इन तीनों बिलों में लिखा हुआ है। बार-बार सरकार बोलती है कि भाई, इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ये प्राईवेट व्यापारी किसानों की उपज लेकर फरार हो गए 2 करोड़ की। नुकसान ये होगा कि आज कंपनियों ने फसल तो लगवा दी और अब क्वालिटी का हवाला देकर उनसे खरीदने में आना-कानी कर रहे हैं। नुकसान ये होगा कि मध्यप्रदेश में 269 सरकारी मंडियों में से 47 परमानेंटली क्लोज डाउन हो गई 6 महीने में, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस के रुप में लग चुका है और इस दौरान हो क्या रहा है, AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड़। जिसको अचानक से उसको बिजनेस मिलता है, अचानक से उसको 30 साल तक के स्टोरेज के काम दे दिए जाते हैं। उसको प्रति टन स्टोरेज का रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता है। उसको 30 साल का ठेका दे दिया जाता है। उसको प्रति टन स्टोरेज का रेवेन्यू इनफ्लेशन से लिंक कर दिया जाता है ताकि रोज-रोज पैसे बढ़ाने के लिए भी आने की जरुरत नहीं है और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के किसान को केन्द्र सरकार द्वारा कहा जाता है, हमारे पास जगह नहीं है, हम आपका चावल रख नहीं सकते हैं। खरीदना तो दूर की बात है, आपके पास वहाँ छत्तीसगढ़ के किसानो के लिए जगह नहीं है, वहाँ खरीदने के लिए और आपने 60 लाख मीट्रिक टन उनसे चावल खरीदने का एक इरादा जाहिर किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बार-बार भारत सरकार के जो पदाधिकारी हैं, भले ही वो कृषि मंत्री हो या वाणिज्य मंत्री हो, उनको चिट्ठियां लिखकर या उनसे मिलकर ये मांग उठाई कि आप हमारा चावल क्यों नहीं खरीद रहे हैं? आपने 60 लाख मीट्रिक टन का हवाला दिया था, अभी तक उनकी इन चिट्ठियों पर, उनके मंतव्य पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जाता है। क्योंकि सरकार तो न्यू ईयर में है, 4 तारीख को बात करेंगे किसानों से क्योंकि 1,2,3 तो हम न्यू ईयर के हैंग ऑवर में रहते हैं।

इस तरह जब बड़े-बड़े हमारे संत समाज के लोग आज किसानों के समर्थन में आगे हैं, जब हमारे 57 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं, फिर भी निष्ठुर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए हमारी मांग है और अब मैं मांग बोलता हूं –

पहली, एफसीआई ने छत्तीसगढ़ में क्यों स्टोरेज से मना किया? क्या इसलिए मना किया कि सूट-बूट के दोस्तों की वहाँ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है?

दूसरा सवाल, क्या किसान अपनी आवाज जो उठा रहे हैं, क्या सरकार उनको पीड़ित कर रही है, उनको दंडित कर रही है अपनी आवाज उठाने के लिए?

मेरा तीसरा कंसर्न है, कांग्रेस पार्टी का तीसरा कंसर्न है - that Why the Government has been in such a rush to award majority of the food grain to their friends? अपने दोस्तों को ये फूड ग्रेन के अचानक से 2017-18 में उस AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड़ को अचानक से क्यों ठेके मिलने चालू हो जाते हैं? क्यों वो कहते हैं कि आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा है, क्यों वो अचानक से अपनी कंपनी को तैयार करते हैं आने वाले भविष्य के लिए?

हम मांग करते हैं कि कृपा करके हमारे अन्नदाताओं के प्रति एंपेथी दिखाएं, एपेथी नहीं। हमारे अन्नदाताओं के प्रति एंपेथी दिखाते हुए हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इन तीनों काले कानूनों को वापस लें, क्योंकि इन तीनों काले कानूनों ने अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया है। मैंने आपको तीन उदाहरण दिए हैं। मध्यप्रदेश में 269 में से 47 कृषि उपज मंडियां, सरकारी कृषि उपज मंडियां परमानेंटली बंद हो गई है। मध्यप्रदेश में 269 में से 143 सरकारी कृषि उपज मंडियों के ट्रांजेक्शन 50 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुके हैं। मध्यप्रदेश में, देवास में जो व्यापारी हैं, वो किसानों के ढाई हजार क्विंटल से ज्यादा दलहन को लेकर, 2 करोड़ जिसका मूल्य है, उसको लेकर गायब हो चुके हैं। मध्यप्रदेश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया है। कंपनियों ने फसल तो लगवा दी, लेकिन क्वालिटी का हवाला देकर अब अन्नदाताओं से वो फसल नहीं खरीदी जा रही है।

असली मंतव्य किसान और भारत का प्रत्येक नागरिक इन तीन काले कानूनों को अब जान चुका है। जब आप अपने दोस्त को रेवेन्यू की गारंटी दे सकते हैं, उसके पैसों को, आप उसको जो रेवेन्यू की गारंटी दे सकते हैं और न केवल गारंटी, इनफ्लेशन के साथ वो पैसा भी बढ़े, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का किसान तो आपसे एक ही बात मांग रहा है कि मेरी फसल की मुझे लीगल गारंटी दी जाए। उसको देने में आपको अभी भी, 39 दिन बीतने के बाद भी आपके कान पर जूं तक नहीं रेग रही है। आप बार-बार उसको नई डेट दे रहे हैं। जब हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि मुझे इन तीन काले कानूनों से नुकसान है और अब तो उदाहरण आने लग गए और आप बार-बार कहते हैं कि हम उसको रिपील नहीं करेंगे, हम उन एक्ट को वापस नहीं लेंगे, संशोधित करेंगे।

क्यों संशोधित करेंगे आप, जब उसका नुकसान हो रहा है किसान को, तो आपको उसको वापस लेना पड़ेगा।

मेरा आप सबके माध्यम से एक सवाल है सरकार से, बहुत वाजिब सवाल पूछ रहा हूं। आप सब लोग बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के। आपने पार्लियामेंट भी कवर की है बहुत वर्षों तक। आप मुझे ये बताईए, ऐसा एक उदाहरण पूरी दुनिया में बता दीजिए, देश नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में, जहाँ पर सरकार एक एक्ट को एनेक्ट करने के बाद एक महीने बाद बोलती है हम संशोधन को तैयार हैं। इसका मतलब उस एक्ट में समस्या है। एक महीने के अंदर आप अगर संशोधन के लिए तैयार हैं, इसका मतलब कि that act had a primary issue with it, उस प्राईमरी इशू को आप रिजोल्व नहीं कर सकते, वो संशोधित नहीं हो सकता है, उसको आप वापस लीजिए और नए कानून किसानों के साथ बैठकर बनाईए। नए कानून संसद में सांसदों के साथ बैठकर बनाईए। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों को निष्काषित करके, ध्वनि मत से कानून मत बनाईए, वोटिंग करवाईए, लोकतांत्रिक पंरपराओं को साथ में लेकर नए कानून बनाईए। ये हमारी मांग है और यही हिंदुस्तान के अन्नदाताओं की मांग है।

Prof. Gourav Vallabh said- A shameful act of Apathy for farmers and Empathy for Suit-Boot friends by the BJP Government.

Today is the 39th day of the fight against apathy. Our 'annadatas' have been sitting out in the cold and rains, fighting to save their dignity as farmers. The one word that the BJP government has justified in the last 39 days is Apathy. One one hand, there has been complete lack of sensitivity towards the plight of the protesting farmers and their demands and on the other, close friends of this BJP government have been receiving complete empathy and blessings for expanding their dominance in all spheres of business.

On one hand, the farmers in return of their protests have only been receiving false promises, the friends have been receiving contracts after contracts to fill their pockets. This is a matter of serious concern as all this is happening as the farmers continue to protest.

<u>Government Fooling the nation</u>

- Adani Agri Logistics Limited (AALL) has been awarded an exclusive service agreement with the Food Corporation of India for storage of foodgrains
- Most of the contracts have been awarded to AALL from 2016 onwards. 8 Projects are Operational as on 31st March 2018 and 9 Projects were Under Construction as on 31st March 2018

- The chronology of AALL gaining stronghold of foodgrains storage in the country is as follows:
    - **2016:** Initial Evaluation by APSEZ of AALL
    - **2017/18:** AALL becomes a sizeable business with new contracts
    - **2017/18:** AALL review of strategy and identification of potential sites for logistics businesses
- AALL handles 5,75,000 MT of food grain for FCI in the states of Punjab, Haryana, Tamilnadu, Karnataka, Maharashtra and West Bengal. Another 3,00,000 MT of food grain is handled for Govt. of Madhya Pradesh. Additionally, AALL has expanded its footprints in Bihar, UP, Punjab, Haryana, Maharashtra & Gujarat
- **The revenues for AALL is guaranteed on INR/Ton based on minimum guaranteed tonnage. When the government can't provide legal guarantee of MSP to the farmers, it is prepared to provide a revenue guarantee to AALL that too with price escalation based on inflation linked formula**
- The guaranteed tenure of such contracts is 30 years

Government Fooling Farmers

- The Food Corporation of India's local Chhatisgarh units have not started lifting the rice stocks yet
- Despite a pre-intimation by the Food Corporation of India (FCI) to procure 60 lakh metric tonne of rice under the central pool for the kharif season, Chhatisgarh has not received a final consent
- The Chhatisgarhstate government started procurement on December 1, and has procured 47 lakh tonnes from 12 lakh farmers so far. But the state is yet to receive a consent from the Government of India, despite several requests over phone. This would impact close to 21.52 Lakh farmers
- Till January 1, the state government had procured 52.64 lakh metric tonne of rice
- Due to FCI not lifting stocks, there is no more space left to stock paddy as well

This is a clear case of complete apathy towards farmers who are fighting for their rights and to save their dignity but the government seems to be occupied in filling the pockets of their friends. If the government is not willing to procure the volumes pre-intimated by them, even when the protests are ongoing, what can we expect from the government once all this settles down? The nation is also coming to a realization that it is only dedicated to filling the pockets of their suit-boot friends and are not procuring grains from states where their friends do not have a presence?

We have three specific questions for the government:

1. **Has the FCI halted procurement in Chhattisgarh because their suit-boot friends are not involved in managing storage in Chhatisgarh and will the procurement only start when their friends get control of storage?**
2. **Are the farmers paying the price for voicing their protests against the farm laws? What about the false promise that the government procurement of foodgrains will continue?**
3. **Why has been the BJP government in such a rush to award majority of the foodgrains storage to their friend who has suddenly emerged as the messiah of storage since the BJP government came to power?**

The government should finally show empathy towards our annadatas, repeal the three laws and provide legal guarantee of MSP to farmers, the same way you have provided to your suit-boot friends.

Sources:

1. https://www.adaniports.com/-/media/Project/Ports/Investor/corporate-governance/Corporate-Announcement/other-intimation--1/24828022019Presentation-on-Acquisition-of-Agri-Logistics-Business.pdf?la=en

किसान आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में प्रो गौरव वल्लभ ने कहा कि हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, हिंदुस्तान के प्रमुख विपक्षी दल के कार्यकर्ता होने के नाते इस सर्दी में आपको विश्वास दिलाकर बोलता हूँ कि मैं आधा घंटा भी इस बारिश और सर्दी में खड़ा नहीं हो सकता, जहाँ पर लाखों लोग खड़े हैं बॉर्डर्स पर। अगर एक घंटा भी हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, तो हमारे अन्नदाता अगर वहाँ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि इन सबका दोषी अगर कोई है, तो वो भारत की सरकार है।

बार-बार मैंने अपनी वार्ता में भी आपसे सवाल पूछा है। पांच दिन का अंतराल क्यों सेकेंड राउंड के लिए, आठवे राउंड के लिए? छठे से आठवे राउंड की बातचीत में 22 दिन का अंतराल क्यों, क्योंकि उनके मन में चोर है, सरकार के। सरकार ने ये सोचा कि थका दो और भगा दो की नीति काम कर जाएगी पर न तो ये अन्नदाता थकने वाले हैं और न हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के 62 करोड़ किसान भागने वाले नहीं हैं। वो वहाँ पर किसी और के लिए नहीं, अपने और अपने परिवार और हिंदुस्तान के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हिंदुस्तान के भविष्य की ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि 30 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर बिजनेस, सालाना जीडीपी में 30 लाख करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो हम नहीं चाहते कि वो चुनिंदा 1-2 दोस्तों को एक प्लेट में सजाकर दे दिया जाए और मैंने आपको एक उदाहरण दिया आज कि 30 साल का ठेका मिल जाता है स्टोरेज का, उसमें इंफ्लेशन लिंक्ड रेवेन्यू बढ़ती रहती है। मैंने आपको उदाहरण दिया, उस कंपनी के जो कि वो सूट-बूट के दोस्त हैं मौजूदा सरकार के। मैंने आपको उदाहरण दिया कि किस तरह वो 16 से, 17 से, 18 से एकदम प्रफुल्लित, पल्लवित हो जाते हैं कि अब तो ये बिजनेस हमको मिलने वाला है इसके अंदर वो किस तरह से एंट्री करते हैं, मैंने आपको सिलसिलेवार और उन्हीं के ये जो आंकड़ा, जो मैंने आपको दिया है, डीटेल्स जो मैंने आपको दी वो उन्हीं का जो प्रजेंटेशन है, जो स्टॉक मार्केट में उन्होंने दिया उसी के हवाले से दिया और कहीं से नहीं लाया गया।

तो मुझे ये लगता है कि किसानों की बात सरकार एंपेथी के साथ, अपना राजहठ को छोड़े, किसानों की बात को समझें, मोदी जी को वाजपेयी जी ने कहा था, राजधर्म का पालन करें। आज वापस वाजपेयी जी तो नहीं हैं, कोई जो बुजुर्ग हैं, अब तो बुजुर्गों को तो उन्होंने भेज दिया, उनकी बात तो वो सुनते नहीं हैं, पर कोई है तो उनको समझाए कि ये राजहठ छोड़ें, किसानों से बात करें, तीनों काले कानूनों को वापस लें और जिस तरह उन्होंने अपने दोस्तों को रेवेन्यू की गारंटी 30 साल तक दी है, हिंदुस्तान के किसानों को भी उनकी उपज के सही मूल्य की गारंटी दें।

On a question about farm laws, Prof. Vallabh said- I think, India is a democratic country and in democracy, the voice of the people is supreme. India is a democracy, where the personal ego doesn't have any space. The voice of the people of the country is supreme and when the voice is from 62 crore Annadata, it is supreme to supreme, so, I think, Government should take a stand, where they should provide justice in the same manner, which they had provided to Adani Agri Logistics Limited, they should give legal guarantee of MSP to the farmers of our country.

Number two, if they want to enact any farm law, please make the provisions after discussing with the farmers and second, once those provisions are made, have a democratic style discussion in both the houses of Parliament. It should

not be, इनको निष्कासित कर दो और मैंने पास कर दिया। This is not the history of India's Parliamentary procedures. We have stalwarts in our Parliamentary democracy. Across the world people used to tell, across the world that India's Parliamentary democracy had the great merits, great discussions, but, it is not the way in which these three black farm laws were enacted, that is not the way. That is not the way that select committees are saying something, सलेक्ट कमेटी का कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए।

I am asking you and I am asking each and every farm union or farmer of this country- can Government name any one farmer, I am not saying 62 crore, any one farmer with whom they had discussed about these three farm laws before making them as an ordinance? Can they name it? They have the affiliate of RSS, Kisan Sangh, had they discussed with them also? You will be surprised, they had not discussed with them also, forget about other people. So, that is not the way and I & Congress Party, we feel that our democracy is very strong and that is the reason, I am of the belief that when the people of the country want something, you are saying that this is going to revolutionies the farmers market or farmers economy in the days to come, but, when farmers themselves are saying that we don't want and for whom? When the major stake holder of the decision is saying- we don't want this reform then this reform is for whom?

जब आप कह रहे हो कि सर, ये आपके लिए अच्छा होगा और मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए, तो फिर किसके लिए? मुझे ये लगता है कि सरकार को एंपेथी के साथ, खुले मन के साथ, अच्छे मन के साथ 4 तारीख को हमारे किसानों की जो दो प्रमुख मांगे हैं, उन दोनों मांगो को मानकर इस आंदोलन को समाप्त करे because, I can tell, ये अमानवीय है, ये अलोकतांत्रिक है, ये बहुत ही निर्दयतापूर्ण रवैया है सरकार का कि अगर हमारे लाखों किसान, दिल्ली के बॉर्डरों पर चारों तरफ बैठे हैं इस ठंड में, इस बारिश में और अगर हम उनकी बात को सुनने के लिए 4 दिन, 5 दिन, 22 दिन का बीच में गैप करते हैं, इससे ज्यादा अमानवीय कुछ नहीं हो सकता।

कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में बीजेपी नेताओं के दिए बयान पर पूछे एक प्रश्न के उत्तर में प्रो. वल्लभ ने कहा कि देखिए, कल जब देश के स्वास्थ्य मंत्री की ज्यादातर इतने बड़े पैंडेमिक के दौरान भी उनकी ज्यादा तस्वीरें लूडो खेलते आईं, पर जब उन्होंने बयान दिया कि सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी, तो हमें लगा कि राहुल गांधी जी की बात का उन पर कोई सकारात्मक असर हुआ, अच्छा भी लगा। उन्होंने कुछ समय बाद अपने बयान को बदल दिया कि नहीं सभी को नहीं, 3 करोड़ लोगों को लगेगा। इस संदर्भ में हमारे 5 प्रश्न हैं – ये जो कुछ समय बाद स्वास्थ्य मंत्री को दिव्य ज्ञान का अवलोकन हुआ, इसके पीछे क्या प्रधानमंत्री जी का दवाब था कि पूरे देश को नहीं लगाना है सिर्फ 3 करोड हैल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को ही लगाना है? **हम ये मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के पटल से कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया का सबसे सर्वोतम वैक्सीन लगना चाहिए।**

हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि जब बिहार चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम समस्त बिहार वासियों को मुफ्त में वैक्सिन लगाएंगे, क्या वो भी एक तरह का 15 लाख वाला ही जुमला था, क्या वो भी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष सृजन करने वाला जैसा ही कोई स्टेटमेंट था?

मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि हम ये पूछना चाहते हैं कि देश के प्रत्येक प्रांत, उस प्रांत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन क्यों नहीं लगाया जा सकता और जब मैं वैक्सीन की बात करता हूं तो मैं कह रहा हूं कि दुनिया का सर्वोतम वैक्सीन क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्यों जब राहुल गांधी जी चेताते हैं कि दुनिया के देशों में जब वैक्सीन लगना चालू हो चुका है, आपको जानकर आश्चर्य होगा इजराइल में तो 11 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन लग चुका है और हम अभी कहाँ खड़े हैं, क्यों हम हर चीज को लेट स्टार्ट करते हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, राहुल गांधी जी के बार-बार चेतावनी देने के बाद कि एक फेयर वैक्सीन, एक इनक्ल्यूजिव कोविड़ वैक्सीन की स्ट्रैटेजी देश को बनानी चाहिए। क्यों हम लेट होते है, क्यों दुनिया के दूसरे देश आगे निकल गए? 27 अगस्त, 2020 का ये ट्वीट है श्री राहुल गांधी का कि कोविड़ वैक्सीन की एक्सेस स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। 27 अगस्त के बाद आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साढ़े 4 महीने हो गए और हम आज भी वहाँ खड़े हैं कि कौन सा वैक्सीन, क्या, किसको लगेगा। रोज नए-नए स्टेटमेंट। **मैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आपको साफ करता हूं और क्लियरी बोलता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक को दुनिया में उपलब्ध सर्वोतम वैक्सीन मुफ्त में लगना चाहिए और हमने तो बड़े-बड़े इम्यूनाईजेशन प्रोग्राम चलाए हैं देश में और हर उन बड़ी-बड़ी महामारियों को, बीमारियों को हमने जड़ से हटाकर दिखाया पूरी दुनिया को, तो क्यों ये सरकार ये चीजें करने में विफल हो रही है?**

मेरा चौथा मंतव्य ये है कि ये चुनावी जुमलेबाजी को बंद करके हर प्रांत के हर व्यक्ति को, हर भाषा के व्यक्ति को, हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति को दुनिया में उपलब्ध सर्वोतम वैक्सीन लगना चाहिए। ये हमारा कहना है।

On another question about Congress Party's stand on Covid-19 vaccine, Prof. Vallabh said- What is our stand is that we have, Congress party have full belief on our scientific community, on our institutions of science. Whatever they are deciding, we are going to follow them, but, we want that the best vaccine after completing all protocols, which are there for those vaccines. When all the countries of the world were fulfilling the protocols, why India had not started, and my question is that. When across the world, people were booking the vaccines, why Government of India had not initiated that process? When the major countries of the world were booking the vaccines, advance bookings were made to those vaccines, why we had not done? Why we had not made a proper Covid vaccine access strategy, inclusive vaccine access strategy for each and every citizen of our country? We are of the belief that all protocols, which are decided by our institutions,

because we have a great belief, because we had made those institutions, people of our country had a great respect for those institutions, we have full belief on our scientific community and doctors, because we are here today after one year of this pandemic, it is because of hard work of our frontline warriors, of our doctors, nurses.

So, we are not having any iota of, I can say distrust to our scientific and the medical community, but, we want the best vaccine, free of charge to each and every citizen of our country after completing all scientific protocols, which are required as per the science and the medical community of our country.

कोविड टीकाकरण से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में प्रो. वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के प्रत्येक नागरिक के लिए है, भले ही वो बिहार में हो, भले ही वो तमिलनाडु में हो, भले ही वो झारखंड में हो, भले ही वो हरियाणा में हो, प्रत्येक नागरिक के लिए मुफ्त टीकाकरण की मांग करती है और ये कोई नाजायज मांग नहीं है। देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और पूर्व में भी हमारी सरकारों ने मैसिव, बहुत बड़े-बड़े टीकाकरण करके बड़ी-बड़ी बीमारियों को परास्त किया।

दूसरा हम ये मांग करते हैं कि दुनिया में उपलब्ध सर्वोतम वैक्सिन देश के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में लगाई जाए।

तीसरा, हम और हमारी पार्टी का विश्वास देश के वैज्ञानिकों पर, देश के इंस्टीट्यूट्शन्स पर, देश के डॉक्टरों पर, देश के फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर निसंदेह है, बिना कोई संदेह है। पर हम ये चाहते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त टीका, बेस्ट टीका और सारे सांइटिफिक, जो हमारी इंस्टिट्यूशन है, उसके प्रोटोकाल को पूरा करने के पश्चात जो टीका आए, वो सबको मुफ्त में बेस्ट टीका लगना चाहिए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग भी है और ये मांग देश के, मैं इसको मांग नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं ये देश के हर व्यक्ति का अधिकार है।

जब दुनिया में बड़े –बड़े देश, जहाँ मोदी जी ज्यादातर भ्रमण करने भी जाते हैं, इजराइल, जब वहाँ पर 11 प्रतिशत जनसंख्या को वैक्सीन लग चुका है और अभी तक हम तैयारियां क्यों नहीं पूरी कर पाए? जब राहुल गांधी जी ने अपने अगस्त के, अपने नवंबर के ट्वीट से बार-बार सरकार को चेताया कि आप एक मैसिव वैक्सीन, इन्क्ल्यूजिव वैक्सीन स्ट्रैटेजी बनाईए, सरकार क्यों नहीं चेतती है? देखिए, कोरोना की महामारी हुई, राहुल जी ने बताया कि ये महामारी होगी, इसका इकोनॉमिक इम्पेक्ट होगा। उसके बाद राहुल जी ने सबसे पहले देश में बताया कि ये जो वैक्सीनेशन है, इसकी स्ट्रैटेजी बनाईए, दुनिया के देश बना रहे हैं, दुनिया के देश वैक्सीन लगा रहे हैं, हमारे देश में क्यों नहीं कर रहे हैं और उस संदर्भ में हम ऐसे विरोधाभासी बयान देखते हैं सरकार की ओर से। सुबह हैल्थ मिनिस्टर बोलते हैं पूरे देश को मुफ्त, शाम को बोलते हैं कि 3 करोड़ लोगों को। ये चेंज क्यों, कौन उनको बोलता है कि 3 करोड़, क्या प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि Health Minister is responsible, is reporting to the Prime Minister of our country. So, because of Prime Minister's pressure, is he changing his statements? हम चाहते

हैं कि सबको लगे। हां, जिनको, जो ज्यादा आयु के हैं, जिनको ज्यादा खतरा है, जो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर हैं, वॉरियर्स हैं, मैडिकल फ्रैटरनिटी के लोग हैं, उनको पहले लगना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर आप बार-बार कभी कहते हैं बिहार में फ्री लगेगा, अब कहते हैं कि सिर्फ 3 करोड़ को लगेगा। कभी कहते हैं कि बिहार को भी नहीं लगेगा। हम तो कहते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को, वो कोई भी प्रांत का हो, वो कोई भी भाषा बोलता है, वो कोई भी धर्म का हो, वो कोई भी आईडियोलॉजी का हो, उसको मुफ्त में दुनिया में उपलब्ध, बेहतरीन, सर्वोतम वैक्सीन फ्री ऑफ कोस्ट लगना चाहिए और वो वैक्सीन हमारी साईंटिफिक और हमारी जो सांईटिफिक इंस्टिट्यूशन हैं, उनके सारे प्रोटोकॉल को पूरा करके वो वैक्सीन उपलब्ध होना चाहिए।

इसी से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में प्रो. वल्लभ ने कहा कि मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। मैं वापस वो बोल देता हूँ, सारे प्रोटोकॉल्स को कंप्लीट करके जो सर्वोत्तम वैक्सीन हो, वो निःशुल्क पूरे देश के हर व्यक्ति को लगनी चाहिए।

एक अन्य प्रश्न पर कि आप कह रहे हो कि सरकार की तैयारी पूरी नही है पर प्रधानमंत्री जी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता ट्वीट कर कह रहे हैं कि वैक्सीन को अनुमति मिल गई है और आगे का रास्ता तय कर रहे हैं, प्रो. वल्लभ ने कहा कि ये आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सिर्फ आज ये देख लीजिएगा जाकर कि दुनिया में अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दुनिया के कितने देशों में वैक्सीन लग चुके हैं और मैंने तो आपको एक देश का आंकड़ा दिया है, जहाँ प्रधानमंत्री जी बीच (Beach) पर टहलते दिखे थे, मुझे दो-तीन वर्षों पहले। मुझे लगा उस देश से कुछ सीखा होगा, उस देश में 11 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आप मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए पर जो आंकड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के देशों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इंक्लूसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू कर दिया और हम अभी तक कन्फ्यूजन की स्टेज में हैं, एक संदेह है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी वित्तमंत्री जी बिहार में बोलती हैं कि बिहार में फ्री हो जाएगा, अब मान लो कोई दूसरे राज्य हों, चार राज्यों में चुनाव होंगे तो वहाँ कुछ और बोल दिया जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार का कर्तव्य सिर्फ अपनी पार्टी को चुनाव जिताना ही नहीं होता है, सरकार का प्रमुख कर्तव्य और मैं कहूँ नंबर-1 कर्तव्य अपने देश के लोगों की जान की हिफाजत करना है।

प्रधानमंत्री जी का एक कथन दोहराता हूँ, जान है तो जहान है। माननीय अब तो जान है तो जहान है, तो हमारे लोगों को सर्वोत्तम वैक्सीन, after completing all protocols जो साइंटिफिक कन्यूनिटी के हैं, उनको पूरा करा कर मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति को लगाने की एक स्ट्रैटजी देश के सामने रखिए। अगर उनको लगता है कि नहीं, वो नहीं कर सकते हैं तो हम तो कहते हैं, पार्लियामेट की एक सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। क्योंकि हमने बड़े-बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए हैं देश में और बड़ी-बड़ी महामारियों को खत्म करके दिखाया है, तो हमारे पास उस चीज का एक्सपीरियंस है, अगर आप चाहते हैं, तो हम आपको उसमें सहयोग भी कर देंगे।

कोरोना टीकाकरण के बारे में समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया के संबंध में पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में प्रो. वल्लभ ने कहा कि समाजवादी पार्टी का ही कोई शीर्ष नेतृत्व उसके बारे में जवाब दे सकता है। हमारी पार्टी का क्या मंतव्य है, हम क्या चाहते हैं, वो मैंने स्पष्ट किया, Free, Inclusive, Best after completing all scientific protocols and it should be

available to everyone in the country irrespective of his caste, colour, creed, religion and ideology.

प्रो. वल्लभ ने कहा कि अंत में ये नए साल की हमारी पहली प्रेसवार्ता थी। मैं आप सबके माध्यम से हिंदुस्तान के सारे किसान भाईयों को हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप अपनी जान का पूर्ण ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मुझे पता है कि आप क्रोध में हैं, आप रोष में हैं, आपकी चीजों को, निर्दयतापूर्ण सरकार आपकी तरफ बात करने से बच रही है, तो अपनी जान की हिफाजत रखें, इमोशनल, या आवेश में आकर कोई भी, किसी भी तरह का गलत कदम न उठाएं।

हम सब आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है और मुझे उम्मीद है कि भारत की, हमारी जो सरकार है, वो कल जो बैठक होगी, उसमें खुले मन से, संवेदनशीलता के साथ निर्णय करते हुए किसान की दोनों मांगो को मानने का काम करेगी और इस तरह का गणित देश को न देगी कि हमने 50 प्रतिशत मांगे मान लीं, 50 प्रतिशत ही रही हैं। इस तरह की नेगोसिएशन की ट्रिक्स हैं, जो किसानों के साथ न खेलें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC